have been gradually picking up. Due to continued economic sanctions against Iraq, normal trade relations with that country cannot be restored till such time the economic sanctions imposed by the UN Security Council against Iraq are lifted. However, export of foodstufs, medicines and items of essential civilian needs to Iraq, is permissible within the parameters of the UN Security Council resolutions in this regard.

(b) As a result of the economic sanctions, exports to Iraq and Kuwait of items like engg. goods, food products, textiles, gem & jewellery etc. came down to Rs. 117.18 crores during 1990-91 (Provisional) as against Rs. 323.63 crores during 1989-90 (Provisional). Project exports to Iraq have also been affected.

India's trade in hard currency

2883. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will be Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to take some steps to have trade in hard currency soon;

(b) if so, what are the details thereof with background for such a step;

(c) whether India would be benefited by this move; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) India's trade is generally transacted in freely convertible foreign currencies (i.e., hard currencies). However, in case of certain countries, India has bilateral clearing arrangements envisaging balanced trade in non-convertible Indian Rupees.

Indo-US Trade Council Chairman's visit to India

2884. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chairman of Indo-US Trade Council visited India recently; and

(b) if so, what are the details of the discussions held and what steps are being taken in pursuance thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) The Indo-US Joint Business Council comprising Indian and US businessmen had its fourteenth meeting on 19-20 November, 1991 in New Delhi which was attended by the Chairman of US-India Joint Business Council. The agenda for discussions included implication for US investment of economic policy reforms in India, technology transfer, multilateral trade negotiations, programmes and policies to promote trade/ and investment, intellectual property protection and view of Indo-US trade.

The Joint Business Council made a number of recommendations on the subject that it discussed. The Indo-US JBC is a non-governmental body.

Export order for leather products

2885. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Minerals and Metals Trading Corporation, New Delhi has received large export orders of leather items including shoes and safety boots, bags and fashionable items;

(b) whether some of the Public Sector Undertakings are also manufacturing such items;

(c) whether Government have taken any decision to utilise the available resources with some Public Sector Undertakings to meet the exporters' requirements of such products; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Minerals and Metals Trading Corporation, New Delhi, has not received any large export orders for shoes, safety boots, bags and fashionable items. However, it has received some trial orders worth around US $ 1,00,000 for leather jackets and executive accessories during the last eight months.

(b) Yes, Sir. The Tannery & Footwear Corporation of India Ltd., Kanpur and the Ordinance Equipment Factory, Kanpur are manufacturing footwear

including boots, military/safety shoes. Leather garments etc

(c) and (d) There is no specific proposal to utilise the resources of the Public Sector Undertakings to meet the requirements of exporters. However, the exporters are free to negotiate directly with these undertakings for utilising their manufacturing facilities, through mutual agreement.

उरुग्वे दौर की वार्ता के उद्देश्य

2886. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उरुग्वे दौर की वार्ता की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और अभिप्राय क्या है;

(ख) उरुग्वे दौर की वार्ता प्रारम्भ करने में किस देश अथवा किन-किन देशों ने पहल की थी और इसमें उनके क्या हित हैं तथा यह पहल किस तारीख को की गई थी;

(ग) क्या उरुग्वे दौर की वार्ता भारत के साथ चल रही है;

(घ) यदि हां, तो कब से और किन-किन देशों के साथ;

(ङ) उरुग्वे दौर की वार्ता में भारत द्वारा क्या अपेक्षा की जा रही है; और

(च) क्या सरकार ने 1992-93 के वर्ष के अपने बजट प्रस्तावों में उरुग्वे दौर की वार्ता में उठाये जा रहे सभी मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया है और किन-किन मुद्दों को अभी स्वीकार किया जाना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) से (छ) वर्ष 1948 में टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गाट) के शुरू होने के बाद से सदस्य देश टैरिफ और गैर-टैरिफ रियायतों के पारम्परिक आदान-प्रदान के जरिए विश्व व्यापार को उदार बनाने तथा गाट के नियमों एवं नियमावलियों में सुधार करने एवं उनका विस्तार करने के लिए निश्चित समयावधि में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं अथवा व्यापार दौर आयोजित करते रहे हैं। अभी तक ऐसे सात दौर हो चुके हैं। गाट के तत्वावधान में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का आठवां दौर सितम्बर, 1986 में उरुग्वे में शुरू किया गया था और यह उरुग्वे दौर के रूप में जाना जाता है।

उरुग्वे दौर के मूल उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके या इन्हें समाप्त करके विश्व व्यापार को और अधिक उदार बनाना, गाट नियमों एवं निगमावलियों को सुदृढ़ बनाना और लागू बहुपक्षीय नियमावलियों के तहत और अधिक विश्व व्यापार को शामिल करना तथा विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति के लिए गाट व्यवस्था को और अनुकूल बनाना है।

1982 में गाट के संविदाकारी पक्षों का मंत्रालयीय अधिवेशन टोक्यो दौर के परिणामों के कार्यान्वयन, और व्यापारिक प्रणाली को प्रभावित करने वाली समस्याओं की जांच करने तथा संविदाकारी पक्षों के बीच सहयोग के लिए भावी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए जेनेवा में हुआ था। इस बैठक में, गाट नियमों और विषयों की प्रभाविता में सुधार करके कृषि को पूरी तरह बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली में लाने और निर्यात प्रतियोगिता को अधिक अनुशासन में लाने तथा साथ ही सामान्य करार के सम्भावित उपयोग सहित वस्त्र तथा परिधान के व्यापार को उदारीकृत करने के उपायों की जांच करने पर सर्वसम्मति थी। इसमें वाणिज्यिक जालसाजी के व्यापारिक पहलुओं पर गैट के ढांचे में संयुक्त कार्रवाई की उपयुक्तता का निर्धारण करने की दृष्टि से नकली वस्तुओं के मामले की जांच करने पर भी सहमति व्यक्त की गई थी। सेवाओं के संबंध में संविदाकारी पक्षों को सूचना की अदला-बदली के लिए आमंत्रित किया गया था और यह परिकल्पना की गई थी कि इसके बाद के अधिवेशन में इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या इस क्षेत्र में कोई बहुपक्षीय कार्रवाई उपयुक्त और वांछनीय है। इस बैठक के बाद में यह बात महसूस की गई थी कि इन मामलों तथा टोक्यो दौर के अन्य अनिर्णित मामलों को उठाने का एक उपयुक्त तरीका व्यापार वार्ताओं का नया दौर शुरू करना है।

उरुग्वे दौर की कार्यसूची तैयारी समिति की जनवरी से जुलाई 1986 तक हुई बैठक में हुए विचार विमर्श के आधार पर सभी भागीदारों के हितों और महत्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी।

उरुग्वे दौर की कार्यसूची पर गाट संविदाकारी पक्षकारों के एक विशेष मंत्रिस्तरीय अधिवेशन में सहमति हुई थी और इसे पुंटा डेल एस्टे घोषणा में मूर्त रूप दिया गया। भारत उरुग्वे दौर में 108 भागीदारों में से एक है।

उरुग्वे दौर का जो चरण 20 दिसम्बर, 1991 को संपन्न हुआ, उसमें इस गतिरोध को दूर करने के लिए बकाया मतभेदों को सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास किया गया। गाट के महानिदेशक श्री आर्थर डंकल ने सरकारों के विचारार्थ एक व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें अब तक हुई वार्ताओं के परिणामों को और जिन क्षेत्रों में भागीदारों के बीच मतभेद बने हुए हैं उनके संबंध में सर्वमान्य हल शामिल किए गए हैं।

अधिकांश भागीदार सरकारों ने डंकल प्रस्तावों पर पूरी तरह संतोष व्यक्त नहीं किया। तथापि, उन्होंने इन प्रस्तावों के आधार पर वार्ता प्रक्रिया को जारी रखने के संबंध में इच्छा जाहिर की है।